

सम्पादकीय

इस कानून में विवाद की स्थिति में मध्यस्थता का भी कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या उसके यूजर को लगता है कि सरकार की फैक्ट चेक यूनिट की बात सही नहीं है तो उसे इसे अदालत में ही चुनौती देनी होगी। तभी ज्यादा संभावना इस बात की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाता ...

यह विशुद्ध रूप से खबर को नियंत्रित करने का प्रयास है। यह प्रत्यक्ष रूप से खबरों को सेंसर करने का प्रयास है। मुख्यधारा की मीडिया पर कमोबेश नियंत्रण के बाद सरकार अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। अभी एक महीना नहीं हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक अंग्रेजी अखबार के कार्यक्रम में कहा था कि फेक न्यूज विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है और साथ ही इससे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है और अब केंद्र सरकार फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए फैट चेक का कानून लेकर आ गई है। सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को लागू करने जा रही है। इस कानून के पहले मसाई में कहा गया था कि प्रेस इंफॉर्मेशन व्यूरो यानी पीआईबी की ओर से बताया जाएगा कि सरकार से जुड़ी कौन सी खबर फर्जी है और उसे सभी प्लेटफॉर्म्स से हटाना होगा। अब सरकार ने इसमें थोड़ा संशोधन किया है। इसमें से पीआईबी को हटा दिया गया है और उसकी जगह सरकार ने एक फैट चेक यूनिट बनाने को कहा है। इस यूनिट की ओर से जिस खबर को फर्जी बताया जाएगा उसे हर जगह से हटाना पड़ेगा। यह कानून लागू होने का मतलब है कि तमाम ॲनलाइन इंटरमीडियरीज जैसे यूट्यूब, फेसबुक, टिवटर आदि से लेकर

सरकार फैक्ट चेक करेगी



की बताई खबर को हटाने का खबरों का स्पेस और कम होगा।

इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को सरकार की फैक्ट चेक यूनिट की बात माननी होगी और उसकी बताई खबर को हटाना होगा। सरकार इसे चाहे जो कहे लेकिन यह विशुद्ध रूप से खबर को नियंत्रित करने का प्रयास है। यह प्रत्यक्ष रूप से खबरों को सेंसर करने का प्रयास है। मुख्यधारा की मीडिया पर कमोबेश नियंत्रण के बाद सरकार अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि वहां सरकार और सत्तारूढ़ दल के आईटी सेल का बनाया नैरेटिव ही ज्यादा चर्चा में रहता है और ज्यादा फेक न्यूज उनकी तरफ से प्रचारित किया जाता है। फिर भी जो थोड़े बहुत स्वतंत्र यूट्यूब चौनल या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको इसके जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। इस कानून में विवाद की स्थिति में मध्यस्थता का भी कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या उसके यूजर को लगता है कि सरकार की फैक्ट चेक यूनिट की बात सही नहीं है तो उसे इसे अदालत में ही चुनौती देनी होगी। तभी ज्यादा संभावना इस बात की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां कानूनी मुकदमों में उलझने की बजाय सरकार का विकल्प चुनेंगे। ऐसे में निष्पक्ष और तटस्थ या सरकार विरोधी होगा।

धार्मिक विवाहों पर सुप्रीम कोर्ट

ममता बनर्जी देश के कई नेताओं के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही हैं। इस क्रम में उन्होंने हाल में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रमुख अधिकारी यादव से भी मुलाकात की थी। सपा प्रमुख ने आने वाले दिनों में विपक्षी गठबंधन के आकार लेने का भरोसा जताते हुए कहा कि 2024 के लोक सभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी...

अजय दीक्षित

सर्वोच्च अदालत में एक न्यायाधीश टिप्पणी की थी कि नफरती भाषण और बयानबाजी दिए जा रहे हैं, क्योंकि राजनपुंसक हैं। राज्य शक्तिहीन हैं। राज्य वर्त पर कार्रवाई नहीं करते। ऐसे नफरती बोल उसी क्षण रुक सकते हैं, जब राजनीति और धर्म को अलग-अलग कर दिया जाए। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीता नागरला ने सवाल उठाया है कि आखिर हमें ऐसा राज्य क्यों चाहिए, जब सब कुछ नफरती हो रहा है? इसकी विवादिती की शनपुंसक वाली उपमा अतिरेकपूर्ण है। कमोबेश लोकतांत्रिक नहीं है। वह राज्य कमजोर, अक्षम, अप्रभावी, अनिर्णयक आया। कुछ भी कह सकते थे, लेकिन शनपुंसक के मायने हैं कि परोक्ष रूप से देश का जनता जिम्मेदार है, क्योंकि लोकतंत्र जनता ही अपनी सरकार चुनती है। नफरती बयानबाजी दो पक्षों के बीच अधिक है। एवं लगातार शहिंदू राष्ट्र बनाने को लोगों का उकसा रहा है। लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है। दूसरा पक्ष ऐसा है, जो शस्त्रकलम तक करने को उन्मादित है। सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि समुदायों की ओर नफरत के बोल अपवाद ही हो सकते हैं। हाल ही में रामनवमी के दिन जुलूस पर कई राज्यों में पथराव किया गया, हिसाँ और आगजनी तक की गई। ऐसा बार-बार होता है, क्योंकि इनके मूल में श्नफरतश है।

परंतु जब समय आएगा तब वे 80 साल के इस आदमी को फिर से चुनाव जिता देंगे। सड़कों पर विरोध और समर्थन में प्रदर्शन होंगे तथा देश और विभाजित हो जाएगा। भारत हो चाहे अमेरिका दोनों में ऐसे नेताओं को चुना जाना बंद होना चाहिए जिनकी उम्र कुछ नहा सौचने और करने की नहीं रह गई है। लोगों को ऐसे हाथों में शासन की बागड़ोर देनी होगी जो अपने जीवन के पांचवें दशक या ज्यादा से ज्यादा...

श्रुति व्यास
अमेरिकी राजनीति में बड़े मियांओं का उन्हें तरह वे अपने 1972 से लम्हे बनते समाप्ति में छापा देने वाले तरह उन्हें जो तर्क उनसे अकलेमिचं तक सही होने वाले इनकी पार्टी बर्नी प्रायरम्भ 81 संकेत की नेतृत्व

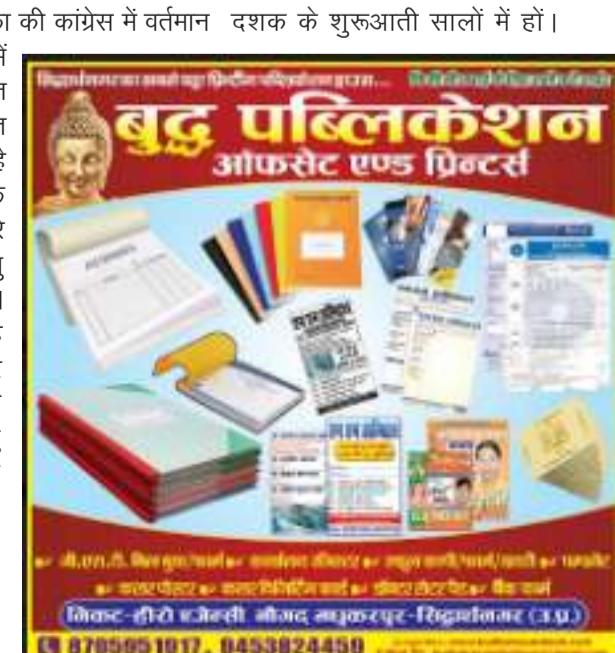
बोलबाला है। इस कदर किसब ठहरा सा, सब कुछ बासा—बासा सा लगता है। और सन 2025 तक तो वहां राजनीति और गतिहीन व सुरक्षा हो जाएगी। जो बाईंडन ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बाईंडन 80 साल के हैं और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपतियों में से एक हैं। उधर 76 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होने की प्रबल सम्भावना है। सो कही अमरीका भी अपने राजनीतिज्ञों की उम्रदराज, बुढ़ा नहीं हो चला है? शक नहीं कि जो बाईंडन ने अपने कठिन कार्यकाल में जबरदस्त सक्रियता व कार्यक्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्हे गंभीर अंदरूनी और बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसलिए उनके राष्ट्रपति बनने के समय से ही यह प्रश्न पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा कि क्या वे फिर राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे? या फिर वे अपनी उम्र के महेनजर चौन की बंसी बजाते हुए इटायर्ड

जुआरने का फैसला लेंगे? आखिरकार जनीति में बहुत समय हो गया है। योग्यता युवावस्था से राजनीति में है। सन् 1984 में वे सीनेट के लिए चुने गए थे। इस नकारात्मक सार्वजनिक जीवन आधी सदी तक हो गया है। अगर वे दुबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो अपने दूसरे कार्यकाल की तक वे 86 साल के हो होंगे। हाल तट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में बिल विलंटन की मेजबानी की न दशक पहले राष्ट्रपति थे किंतु बारासाल छोटे हैं। और जो बार्डइडन नहीं हैं। सीनेट के रिपब्लिकन सदस्य कोनेल 81 साल के हैं? उनके नाम के इतिहास में सबसे अधिक अवधि दरस्य रहने का रिकार्ड है। वे रिटायर मूड में कर्तव्य नहीं हैं। चक शुमर, दो सदन में बहुमत प्राप्त डेमोक्रेटिक नेता हैं, 72 साल के हैं। सीनेटर डंडर्स, जो पिछली दो डेमोक्रेटिक ज भी 80 साल के ए स्वरथ और फूर्तीले पुरुष हैं जो राष्ट्रपति पद से जुड़े सभी दायित्वों का निर्वहन करने वाले हैं। पिछले साल तक 82 वर्ष के पिलोसी हाउस थ्रॉफ चिपेज्जेटिस

कुण्डलियत और ठहरा, यका अमेरिका!

अनुसार उनकी जीन्स इतनी अपूर्व और असाराण हैं कि यदि वे अपने खानपान का थोड़ा सा भी ख्याल रखते तो कम से कम 200 साल जीते। अपनी रिपब्लिकन पार्टी से जैनेता ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं उनमें हैली वे अलावा फ्लोरिडा के 44 वर्षीय गवर्नर रोन डेसाटिस, पूर्व विदेशमंत्री माईक पोमपियो जैसे 59 साल के हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति माईक पेन्स जैसे 57 साल के सीनेटर टिम स्काट, शामिल हैं जैसे तो 82 और 77 साल के ये बड़े मियां फिर संघर्ष चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? एक कारण सत्ता प्रेम हो सकता है। जहां तक ट्रंप का सवाल है, वे सत्ता से दीवानगी की हद तक प्रेम करते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि अमरीका राजनीतिज्ञ यह मानते होंगे कि उम्र रिटायरमेंट का कारण नहीं हो सकती बल्कि वह तो उन्हें सत्ता में रहने के लिए और सुपात्र बनाती है। हमारे अधिकांश नेता खासे बुजुर्ग हैं। बहुत से 70 के पार हैं और कुछ 80 के पार भी। परंतु रिटायरमेंट के बावें में शायद वे सोचते ही नहीं हैं। वे दिन-रात सत्ता के पीछे भाग रहे हैं और युवाओं के शपथ्य और श्वशंवाद के लाभार्थीय ठहरा रहे हैं। सत्ता हासिल करने के लिए वे देश के बांटने के लिए तैयार हैं, जैसे इस समय अमेरिका बंटा हुआ है। ऐसा कहते हैं विनोद सत्ता भ्रष्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है विनोद सत्ता, 70 साल के बाद व्यक्ति के दिमाग के भी भ्रष्ट कर देती है। कई लोग कहते सन्

The image consists of two parts. The left side shows a black and white photograph of a newspaper page with several columns of text in Hindi. The right side is a full-page color advertisement for a printing company. The ad features a large statue of Buddha at the top left. Below it, the company's name 'बुद्ध पब्लिकेशन' is written in large, bold, yellow and red letters. The central part of the ad displays various printed products including books, brochures, and business cards. At the bottom, there is contact information: 'मोबाइल-टीवी चैनल सी. बी.एस. लक्ष्मणपुर-रिंगड़ालगढ़ (उ.प.)' and a phone number '9710991817, 0433324450'. The background of the ad is light blue.



हैरी बुक की प्रतिभा से सभी वाकिफ हैं: Markram

सनराइजर्स हैदराबाद के पिछले मैच में पांच छक्के जड़कर उन्हें हराना अच्छा रहा। हमने कप्तान एडेन मार्कर्सन ने शुकवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग में जीत दर्ज करने के लिए गेंदबाजों की प्रशंसा की और साथ ही कहा कि हर कोई इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ल्क की प्रतिभा से वाकिफ है जिन्होंने 2023 चरण का पहला शतक जड़ा। ल्क के नावाद 100 और मार्कर्सन के 50 रन से सनराइजर्स हैदराबाद ने चार विकेट पर 228 रन का विराट स्कोर खड़ा किया। ल्क ने 55 गेंद में 12 चौके और तीन छक्के जड़े। मार्कर्सन ने मैच के बाद कहा, "गेंदबाजों को सलाम, जिन्होंने शानदार जज्बा दिखाया। उनके बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए यह स्कोर भी सुरक्षित नहीं था।" कप्तान नीतिश राणा की 75 रन और कहा, "उनके घरेलू मैदान में यह मुश्किल विकेट था। हमने



कुछ क्षेत्रों पर काम करना है। बल्लौर टीम सुधार करना अच्छा है। उम्मीद है कि यह लय जारी रहेगी।" सनराइजर्स हैदराबाद ने क्षेत्रक्षण के दौरान कैच के कई मौके गंवाये, वर्ना केकेआर की टीम इस स्कोर तक नहीं पहुंची होती है। वहीं 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे ल्क ने कहा, "यह विशेष रात है, थोड़ा तनाव था लेकिन जीत दर्ज करना अच्छा है।" कंकेआर के कप्तान राणा ने कहा, "हम अच्छी शुरुआत की और हमारी योजना के अनुसार गेंदबाजी नहीं कर पाये, हम और बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। रिकू और मैं ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे खुश हूं।"

उन्होंने कहा, "भुवी भरोसेमंद खिलाड़ी है, गेंदबाजों के लिये निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 205 रन ही बना सकी और 23 रन से हार गयी। मार्कर्सन ने कहा, "उनके घरेलू मैदान में यह मुश्किल विकेट था। हमें

डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की संरचना समावेशी, विकास को मिलती है तेज़ी: सीतारमण

वाणिगठन। वित्त मंत्री निर्मला कहा कि पिछले दो वर्षों में भारत



सीतारमण ने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे (डीपीआई) के प्रारूप के समावेशी बताते हुए कहा है कि यह देशों की विकास प्रक्रियाओं को गति देने और अधिकतम लाभ पहुंचाने में मददगार हो सकते हैं। सीतारमण ने शुकवार को यहां मुद्राकोष की तरफ से मैं डीपीआई ने लक्षित, त्वरित एवं डीपीआई पर आयोजित एक सक्षम सेवा देने में बड़ा योगदान दिया है। इन डिजिटल बुनियादी ढांचों से भारत आबादी के बड़े हिस्से तक प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में मजबूत, समावेशी, जुझार एवं सफल रहा है। इस अवसर पर डिक्टेटर द्वारा दिक्षित ढांचे से अंजाम देने पर अधिक जोर देते हैं।

सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के सहयोग से तेयार डीपीआई पहुंच से बाहर के लोगों तक पहुंचने के लिए विकास को बहुत तेज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत जैसे देशों के अनुभवों से सबक लिया जा सकता है। इंफोसिस के सह-रसंशापक नंदन नीलकणि ने कहा कि भारत में डीपीआई के सफल होने के पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति एक बड़ा सुविधाओं की तरह, यह विशेष रूप से डिवटर ल्यू सबक्साइबर के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री द्वारा इत्यादि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा द्वारा दिनांक: 27.04.2023 को अपराह्न 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 11.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक: 27.04.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय गदहमरवा में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :-1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति सलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर कलीयरेन्ससंलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेंडर खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थलपर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है, आपूर्तिकर्ता को 2. 24प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों सचिवों सदस्यों बी.डी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सभी सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मात्रा नहीं होगा। 10. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडी एवं एनएससी/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत गदहमरवा के नाम बच्दक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13. निविदा फार्म ग्राम पंचायत गदहमरवा कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/- रुपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्त व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत गदहमरवा के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यालय : ग्राम पंचायत-गदहमरवा विकास खण्ड-लोटन बाजार.जनपद-सिद्धार्थनगर

-:अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना:-

वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा योजना/राज्य वित्त/चौदहवां/पन्द्रहवां वित्त/पिछले क्षेत्र अनुदान निधि/पंचमार्यज्ञवित्त,पंचायत भवन/अन्तर्य स्थल/विधायक निधि,सांसद निधि,गोवंश आश्रय केन्द्र व अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों की सामग्री जैसे प्रथम श्रेणी,इंट की गिरी, मोरंग बालू,सादा बालू,सीमेंट,सीमेंट इंट,सरिया,ह्यूम पाइप,विद्युत के समान,सफाई सामग्री,पैट,टाइल्स, साइन बोर्ड इत्यादि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा द्वारा दिनांक: 27.04.2023 को अपराह्न 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 11.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक: 27.04.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय गदहमरवा में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :-1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति सलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर कलीयरेन्ससंलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेंडर खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थलपर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है, आपूर्तिकर्ता को 2. 24प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों सचिवों सदस्यों बी.डी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सभी सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मात्रा नहीं होगा। 10. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडी एवं एनएससी/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत गदहमरवा के नाम बच्दक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13. निविदा फार्म ग्राम पंचायत गदहमरवा कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/- रुपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14. सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्त व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत गदहमरवा के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नियम व शर्त :-1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति सलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर कलीयरेन्ससंलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्र

